>

Title: Need to take necessary steps to accelerate the process for implementation of high-speed rail project between Delhi and Meerut.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): वर्ष 1985 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) का गठन करने का एक उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर बढ़ रहे दबाव को भी कम करना था तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एन.सी.आर. में आने वाले प्रमुख नगरों को दिल्ली से रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जोड़ने की योजना थी ताकि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग एक घंटा या उससे कम में दिल्ली पहुँचकर दिनभर अपनी नौकरी, व्यवसाय इत्यादि कार्य करके अपने घर वापस लौट जाएं। इस दृष्टि से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगरों को दिल्ली से जोड़े जाने संबंधी कार्यों की घोर उपेक्षा हुई है। 28 वर्ष बीत जाने के बावजूद न तो दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस हाइवे बना है तथा न ही दिल्ली-मेरठ को जोड़ने वाली हाईस्पीड ट्रेन संबंधी कार्य में कोई उल्लेखनीय प्रगति हुई है। एन.सी.आर. के नगरों को दिल्ली से हाईस्पीड ट्रेन से जोड़ने के लिए केन्द्र सरकार ने एन.सी.आर. ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का गठन तो किया है परंतु एन.सी.आर.पी.बी., एन.एच.ए.आई. इत्यादि पक्षों में आपसी तालमेल एवं सहमति न होने के कारण यह कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एन.एच.ए.आई. के सदस्य-सचिव के अनुसार दिल्ली के निजामुद्दीन से मेरठ के पल्लवपुरम तक हाईस्पीड ट्रेन के ट्रैक का रूट एन.एच.-58 पर डिजाइन किया गया है तथा एन.एच.ए.आई. ही इस राजमार्ग को संकरा बताकर इसे अव्यवहारिक बता रहा है। अब इस ट्रेन का नया एलाइनमैंट स्वीकृत किया गया है परंतु कुल मिलाकर दिल्ली-मेरठ हाईस्पीड ट्रेन की योजना विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की बैठकों से आगे नहीं बढ़ पा रही है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इसमें तुंत हस्तक्षेप करे तथा दिल्ली-मेरठ हाईस्पीड ट्रेन के मंदगति से चल रहे प्रोजेक्ट की स्पीड बढ़ाए ताकि इस बहुप्रतीक्षित योजना पर कार्य आरंभ हो, हाईस्पीड ट्रेन चल सके तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास को गति मिल सके।